MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

REPORT OF THE BERI COMMISSION

6. SHRI M. K. MOHTA:f SHRI NIRANJAN VARMA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Beri Commission appointed by Government to enquire into the police firing in March, 1967 on the eve of Ministry formation in Rajasthan after the last General Elections have held that the firing was 'unjustified';

(b) whether a report of the Commission will be laid on the Table of the House; and

(c) the steps proposed to be taken by Government on the recommendations | findings of the Commission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME: AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) The Commission has held that the firing in Johri Ba/ar on 7th March 1967 and the firing at Sirehdeodi Bazar were unjustified. The firing at the Kotwaii was held to be justified.

(b) No, Sir. The report has been placed on the table $_0$f tne Rajasthan Legislative Assembly and i$_s$ now a public document.

(c) State Government is examining the report. It is for the State Government to take appropriate action in this behalf.

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri M. K. Mohta.

SHRI M. K. MOHTA: Sir, this is an extremely serious matter because not only has Justice Beri termed the firing as unjustified, as stated by the hon. Minister, but the Commission has also said that the evidence by the Government or the authorities has been proved to be wrong. For instance, the number of rounds fired was held to be not 39 as claimed, but 80, and the duration was not 15 or 20 minutes, but two hours and 45 minutes. Even the ambulance was fired upon recklessly. So in view of the findings of this Commission, I would like to ask the hon. Minister whether it is a fact that in a conference of Chief Justices of High Courts, it was decided that no High Court Judge will be permitted to act as Commissioner under the Commission of Inquiry Act unless the concerned Government undertakes to implement in toto the findings of the Commission. If so, did the Chief Justice of Rajasthan seek such an assurance and was such an assurance given and, if so, when, by whom, and whether in writing or orally' And will the hon. Minister agree to place on the Table of the House a copy of such an assurance?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, when the Chief Secretary of the Rajasthan Government wrote to the High Court requesting them to nominate a judge for holding this inquiry, the Registrar of the High Court after some time suggested the name of Justice Beri for this inquiry and also drew the attention of the Rajasthan Government to this Resolution of the Chief Justices' Conference. They did not seek any specific commitment from the Rajasthan Government (hat the findings of the Commission will be accepted or otherwise. They only drew attention to this and also enclosed a copy of the Resolution that was passed bv the Chief Justices' Conference. That is about nil that was done as far as this particular matter is concerned.

SHRI M. K. MOHTA: Sir, I would like to ask the hon. Minister as to what the constitutional position or convention or practice is on this question of implementation by a successor Government of the assurances or commitments given by the previous Government. And in view of the statement of Shri Damodardas Vyas, Home Minister of Rajasthan, that the present State Government is not bound by the assurances of the previous Government regarding the implementation of the Beri Commission Report in toto, what steps does the hon. Minister contemplate taking in the matter to ensure natural justice and fair play?

SHRT VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I do not think that any such statement has been made by the Home Minister of Rajasthan that he is not bound by the commitment made by the previous Government. But in any case, I shall check the position. As far as action on the report is concerned, I have already indicated that the action has to be taken by the Rajasthan Government.

श्री निरंजन वर्मा : क्या श्रीमान् यह बताने का कष्ट करेंगे कि बेरी कमीशन जो इस बात की जांच करने के लिये आधारित था कि वहां पर जो पुलिस की अंधाधुंध गोलियां चलीं थीं उस में बहुत से आदमी मारे गये थे और गवर्नमेंट के वर्णन के अनुसार तो नहीं, वैसे साधारण जनता के अनुसार बहुत से व्यक्ति मारे गये थे, तो उन के मुआवजे के बारे में और जिन व्यक्तियों ने कानून से विरत हो कर , दूर रहकर, जो अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं, ऐसे व्यक्तियों को दंड देने के लिये , क्या आप इस सदन को आश्वासन देंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार दंड देने के लिये कतरा रही है, और मुआवजे के प्रश्न पर भी वह बहुत अच्छा रुख अख्तियार नहीं कर रही है। इसलिये क्या आप यह सजेस्ट करेंगे कि जिसतरह से बेरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भावनाएं व्यक्त की हैं उसी के अनुकूल वह आचरण करेंगे और विशेषत: ऐसी स्थिति में जब कि वहां पर कल से विधान सभा के सदस्यों ने धरना दिया हुआ है कि गवर्नमेंट इस बात से कतरा रही है कि बेरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो निर्णय दिये हैं उन को वहां की सरकार लागू नहीं कर रही है । तो क्या उसको लागू करने के लिये आप कहेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान सरकार बेरी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में हिचकिचाहट कर रही है । हम लोगों को राज्य सरकार से जो सूचना मिली है उन के अनुसार तीन अफसरों की कमेटी बनी है, फालो आप ऐक्शन करने के लिये, यह देखने के लिये कि क्या कुछ किया जा सकता है । जहां तक हर्जाने का सवाल है उसके बारे में भी वह कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की तरफ से यहां कोई आश्वासन नहीं दे सकते क्योंकि हम लोगों का संबंध ऐसे काम से नहीं आता है । राजस्थान असेम्बली में इस बारे में प्रश्नोत्तर हुए, वहां क सदस्यों ने इस बारे में वहां की सरकार से जांच पड़ताल कराई है और सरकार जो भी कार्यवाही कर रही है उस के बारे में वहां के विधान सभा के सदस्यों को सूचित कर रही है । उनके बदले हम यहां बैठकर काम करने लगें, यह मैं नहीं समझता उचित है ।

श्री राजनारायण : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि बेरी कमीशन की जो रिपोर्ट होगी उसको

पूर्णतः लागू किया जायेगा । दूसरी बात, क्या सरकार को इस बात की जानकारी अब तक नहीं हो पायी कि निश्चित रूप में श्री दामोदरदास व्यास ने कहा कि हम सक्सेसर गवर्नमेंट हैं, हमारी पहले की सरकार ने अगर कोई वायदा किया है तो उसके मुताबिक चलना मेरे लिये कोई वैधता नहीं है । तो दामोदरदास व्यास का यह वक्तव्य स्पष्ट है । क्या कमीशन की रपट में यह बात भी सरकार की जानकारी में आई है कि कमीशन ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि जब दफा 144 हटा ली गई थीं, उस के पहले दफा 144 लगी थी, तब वहां पर कोई टेन्शन नहीं था, कोई उत्तेजना नहीं थी । इस के बाद वहां पर फायरिंग हुई, दफा 144 के बाद तो क्या बेरी कमीशन ने यह भी लिखा है कि जितने राउन्ड गोली सरकार कहती है चली इस बात पर मेरा यक़ीन नहीं है, इससे ज्यादा राउन्ड गोली चलीं ? क्या बेरी कमीशन ने यह भी लिखा है कि जितनी मृत्यु बताई गई उन से ज्यादा मृत्यु हुई, ऐसा मेरा निष्कर्ष हो रहा है । ये तमाम बातें जो हुई हैं । बेरी कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी अंधाधुंध निरंकुश, , बर्बर गोली शायद कभी न चली हो, लोगों को घेर घेर कर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, दुकानों में घुस घुस कर मारा गया है, और बेरी कमीशन कहता है कि वहां पर भीड़ कुछ थी नहीं, कोई नहीं था--यह क्यों ? यह लोगों को आतंकित करने के लिये, परेशान करने के लिये, एक प्रकार से सुखाड़िया के हाथ में फिर यहां की सरकार आ जाये उसकी एक साजिश और तिकड़म है और क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वहां सारी की सारी रेस्पांसिबिलिटी हो जाती है इस फायरिंग की वह सुखाड़िया पर जाती है । श्रीमन्, अगर इतनी भयंकर अनर्थकारी गोलीवर्षा के हो जाने के बाद भी सुखाड़िया साहब इस्तीफा नहीं देते तो उनके जनतंत्री बुद्धि और काम को हम सब लोगों को कोसना चाहिये और उसकी भर्त्सना करनी चाहिये । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह सरकार गोली कब चले, किस अवस्था में चले, किन पर चले, उसे पूरी मान्यता देने के लिए सुखाड़िया सरकार को जिम्मेदार समझकर उनको बाध्य करे कि वे इस्तीफा दें। क्योंकि जनतंत्र में जिस ढंग से निहत्थी जनता पर गोली जयपुर में चलाई गई वह जनतंत्र के लिये एक कलंक है और इस तरह की गोली कहीं भी नहीं चलनी चाहिये । इसलिए माननीय मंत्री जो मेरे सब सवाल का उत्तर दें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक राज्यपाल के आश्वासन का सवाल है, मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई आश्वासन उस समय दिया गया । जहां तक वहां के गृह मंत्री श्री दामोदर व्यास के वक्तव्य का सवाल है, मैं इस सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं । जहां तक बेरी कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है और माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह रिपोर्ट सब के सामने है । ऐसी बहुत सी बात माननीय सदस्य ने कहीं हैं जो कि उस में हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं । पर इस में सवाल असल यह आता है कि इसके ऊपर अब क्या कार्यवाही की जाय इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कार्यवाही करने की जिम्मेदारी है, वह वहां की स्थानीय सरकार की है। जिस तरह की सूचना उन्होंने हमारे पास भेजी है, उस से लगता है, कि वे गम्भीरता पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक उसके ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं और मुझे इस बात की पूर्ण उम्मीद है कि उनकी कार्यवाही से सब लोग सन्तुष्ट होंगे ।

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: This police firing took place on the peaceful demonstrators who were demonstrating against the Governor . . .

SHRI RAJNARAIN; No, no . . .

{Interruptions)

SHRI MULKA GOVINDA REDDY: I would like to know from the Minister as to what is the general attitude of the Government whenever a commission has been appointed under the Commissions of Inquiry Act, whether they accept the report of that commission as an award or in what manner they are going to treat that report.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, our general attitude towards that report is that of respect and we always try to accept the recommendations of such a commission to the extent it is feasible and possible.

SHRI LOKANATH MISRA: Sir, may I know from the hon. Minister whether our police force is still guided by the Indian Police Force Act of 1888 and, if so, whether section 3 of that particular Act belonging to the 19th century says that no particular State can have the police force from another State without explicit orders? May I also know whether it was not a fact that the police force from Madhya Pradesh and Uttar Pradesh were brought into Rajasthan and put into use and, if so, who had ordered for that police force to be brought down to Rajasthan and to be used?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, it is a fact that our police force is guided by that Act. I do not know in what year that particular Act was passed. And as far as the other matter is concerned, I will look into it. I have no information about it.

SHRI B. K. KAUL: fe the Government aware that it was stated by the Commission that there was no conspiracy between Shri Mohanlal Sukhadia and others . . . (Interruptions), to invite President's rule in Rajasthan in furtherance of which firing was done in Johri Bazaar and elsewhere? I would further quote the observations of Justice Beri about the situation which was created . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: We would like the report to be placed on the Table of the House.

SHRI B. K. KAUL: He says . . .

MR. CHAIRMAN; You put a question.

SHRI B. K. KAUL: I would like tc enlighten the House of certain facts.:

MR. CHAIRMAN: But do not refer to the report. You put a question.

SHRI B. K. KAUL: Is it not a fact that Justice Beri has said in his report that all this upheaval and the rioting condition which was created there, was the result of speeches made by Her Highness Rani Gayatri Devi and other opposition members . .

SHRI A. G. KULKARNI: Why Her Highness? What is Her Highness? There is no Her Highness or His Highness nowadays. Say "Rani Gayatri Devi". All are Indian citizens.

SHRI B. K. KAUL: For day« together they had been using all types of things inciting violence and they had been doing all those things even before the elections. So, his observation is that it was easier to excite the people, the masses, but the leadership failed to bring them round to their viewpoint. In view of that, when a situation like that was created, would it not be desirable to quell that disturbance by whatever means possible at that time?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I am not called upon to give an opinion about that particular situation. The honourable Member has quoted something from the report. The report is a public document and it is well-known to everybody. I have no comments to make on that.

श्री राज नारायण : श्रीमन्, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है, । जब हमने यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट इन टोटो लागू होगी ? तो मंत्री जी ने यह कहा कि जहां तक मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है । अब हमारे पास लोगों ने जो कागजात भेजे हैं, जो कुछ लिखकर भेजा है, उस को हम आपके सामने पढ़ देते हैं ।

MR . CHAIRMAN-. How can you receive some information from the Rajasthan people? Anfl vou want to quote it.

श्री राजनारायण : हम लोगों की भी पार्टी राजस्थान में एक जिन्दा पार्टी है ।

MR. CHAIRMAN: How is it relevant? Put a question. Do not read it.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मेरा एक प्वाइन्ट है । अभी मंत्री ने कहा कि ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है । तो यह 13 मार्च, 1967 को गवर्नमेंट ने राजस्थान हाईकोर्ट को जो कमिटमेंट दिया है, उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं ।

"The Governor made a commitment on 31st March, 1967 to the High Court of Rajasthan that the report of the Commission would be accepted *in toto.* This commitment was in black and white and it is still on the record of the High Court. But Shri Damodar Das Vyas, Home Minister of Rajasthan, stated in the Assembly on llth March, 1569 that first of all, the Government had not given any such commitment to the High Court and, if however, it was taken for granted that such a commitment was made, they were not ready or bound to honour such commitment on account of the following reasons:—

The commitment was of the former Government working under the President's rule. The commitment was in contravention of the provisions of the Commissions of Inquiry Act."

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि हमारे पास यह पूरी रिपोर्ट है । इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के गृह मंत्री श्री दामोदर व्यास ने कहा कि वे इस चीज को मानने के लिये तैयार नहीं हैं । इसके बारे में गृहमंत्री जी यह कहते हैं कि हम को इसके बारे में मालूम नहीं है कि दामोदर व्यास जी ऐसा कहते हैं : तो मैं आपके सामने माननीय गृह मंत्री जी के विरुद्ध प्रिविलेज मोशन रखना चाहता हूं कि श्री विद्याचरण शुक्ल जी ने जानबूझकर हाफ ट्रुथ बात कह कर सदन को गुमराह किया ।

Wilful suppression of truth is contempt of the House and any comtempt }f the House is a breach of privilege.

इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि आप इस बात को नोटिस में लेकर जहां इस तरह से सदन को गुमराह किया गया हो, वहां विशेषाधिकार अवहेलना का प्रस्ताव रखने का मुझे मौका दें क्योंकि इस तरह की चीज सदन में हो रही है । इस चीज पर जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है और मुझे आप प्रिविलेज मोशन रखने की इजाजत दें ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है । हमें जो सूचना राज्य सरकार से मिली है वह सूचना आपके सामने रख दी है और उनकी सूचना के अनुसार जो बातें माननीय सदस्य कह रहे हैं, वे गलत हैं ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है कि बेरी कमीशन की नियुक्ति के लिये राष्ट्रपति महोदय ने आदेश दिया था और राष्ट्रपति महोदय के आदेश के बाद ही बेरी कमीशन की नियुक्ति हुई । दूसरे जैसा कि माननीय मंत्री जी ने खुद माना है कि जब चीफ जस्टिस, राजस्थान हाई कोर्ट ने बेरी साहब की नियुक्ति की बात स्वीकार की तो जजेज कांफ्रेंस में स्वीकार किये गये प्रस्ताव की प्रतिलिपि, जिस में इस बात का उल्लेख है कि इस प्रकार नियुक्त किये गये कमीशन की रिपोर्ट पूरे तौर पर मानी जायगी तभी कोई जज नियुक्त होगा, उसके साथ संलग्न थी, इस से क्या यह अर्थ नहीं निकलता कि सरकार ने जब बेरी साहब को नियुक्त किया तो उस शर्त को स्वीकार कर के किया । अर्थात् राजस्थान सरकार के द्वारा यह कमीशन नियुक्त नहीं है । राजस्थान सरकार की मर्जी के विपरीत यह कमीशन जांच करने के लिए बैठा । विशेषकर जब कि इस कमीशन ने सरकार के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को अमान्य किया है तो फिर यह अपेक्षा करना, कि राजस्थान सरकार इसको कार्यान्वित करने के लिये कदम उठायेगी, इसके बारे में केन्द्रीय सरकार किस प्रकार से आश्वस्त है ? जिन कर्मचारियों पर बेरी कमीशन ने आरोप लगाया है, राजस्थान सरकार ने उन कर्मचारियों को पहले ही से प्रोमोट कर दिया है । जब अब सरकार के द्वारा ही नियुक्त किये गये कर्मचारी इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के बारे में किस प्रकार से न्याय कर सकेंगे । राजस्थान सरकार द्वारा तथ्य झुठला दिये गये हैं, राजस्थान सरकार के अधिकारी जिन पर इल्जाम है कि उनको पहले ही प्रोमोशन दे दिया गया है और इस लिये अब कोई आशा नहीं है कि राजस्थान सरकार इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करेगी । इसलिये यह मांग है कि क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति के द्वारा आदेशों से निर्मित किये हुये इस कमीशन की रिपोर्ट पर, खुद कुछ कदम उठाने के लिये तैयार होगी और जुडीशियल इक्वायरी इस्टिट्यूट करायेगी इसको आगे चलाने के लिये ? इस में जो फाइंडिंग्स अधूरी रही हैं और इस कमीशन के अन्दर जिन की तरफ से संकेत किया गया है जैसे सिरेहदेओ बाजार में गोली किसने चलाई इसके बारे में इस कमीशन के सामने कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये, जब इतना बड़ा लेक्युना जांच में हो, तो क्या केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी इस जांच को पूरा कराने के लिये और इसको फालोअप एक्शन को करवाने के लिये अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस आयोग की नियुक्ति उस समय हुई जब राजस्थान में अस्थायी रूप से राष्ट्रपति शासन चलता था । उस समय राज्य शासन के द्वारा इस आयोग की नियुक्ति की गई थी ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया था ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत जो वहां स्थानीय प्रशासन था उसके द्वारा इस आयोग की नियुक्ति की गई थी । उसके बाद वहां पर लोकप्रिय सरकार की पुनः स्थापना हुई । जो इस कमेटी की रिपोर्ट आई उसके संबंध में वहां पर स्थानीय सरकार की इस बात की जिम्मेदारी है, वहां पर विधान

सभा की इस बात की जिम्मेदारी है कि वह इस पर जांच पड़ताल करे और जो करना हो उस पर सोच विचार करे। हमें अपने ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिये जिसे से उनकी जिम्मेदारी में कमी आये या उनकी जिम्मेदारी में खलल पड़े या इंटरफीयरेंस हो। मैं नहीं समझता कि प्रजातांत्रिक ढंग से कोई इस तरह काम किया जा सकता है जैसा कि माननीय सदस्य सोचते हैं।

SHRI B. K. KAUL: I want to put an important question.

MR. CHAIRMAN: It may be very important but I must also conduct the business of the House. This is the last question. Mr. Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am basing my supplementary on what he has said and on the question. The Minister himself has admitted that when a request was made to the Chief Justice of Rajasthan to nominate a person to be the Head of the Commission, the Registrar of the High Court informed the Rajasthan Government two things;

(1) That the Chief Justices Conference has adopted a Resolution that in the event of any Judge being appointed as the Chairman of the Commission, his recommendation should be accepted in toto.

(2) A copy of the Resolution of the Chief Justices Conference was also sent.

It follows clearly that the acceptance of the offer was conditional upon the Government's acceptance of the two conditions I have mentioned, namely, the decision of the Chief Justices Conference. That is how the Judges would speak. They would not bargain with the Government. It is clear that when after receiving the documents Mr. Beri was appointed as the Commissioner and assigned the task of enquiry, the Government accepted the condition that the recommendations would be implemented in toto.

SHRI M. N. KAUL: No.

SHRi BHUPESH GUPTA: I am putting it to you. This is a serious matter. The Registrar of the High Court sends a copy of the Resolution, communicates the decisions and after that the Government accepted him as the Commissioner; it follows that they accepted the other things also.

SHRI M. N. KAUL: They could have put it expressly in their letter.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am a Private Member of Parliament and you were an official of the parliament. We do not know. Nobody writes like that. It is a very polite, dignified way of telling the Government: 'We are, as Chief Justices and Judges, under a commitment to the Resolution passed by the Chief Justices Conference'. Suppose you offer your daughter in marriage to somebody and then send along with it a condition as an obligation and the bridegroom accepts it, how should I take it? Therefore it is quite clear that the Judges behaved in a dignified way. The Central Government cannot escape its responsibilities by saying that it is a task of the Rajasthan Government.

In view of the fact that it took place at a time when the Central Government was very much in the picture and also in view of the fact that it was done under a Central Act and also in view of the fact that the person involved was a Judge, why the Central Government did not issue a directive or tell in writing the Rajasthan Government that in the light of the circumstances of the case, the recommendations should be accepted in toto. Do I understand that the Central Government is not doing it because the Rajasthan Government if this had happened in • either happen- to be a Congress-run Government? What would have happened

Kerala or West Bengal? Mr. Chavan would have sent letters after letters and issued them to the press in order to pressurise the State Government.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The relevant portion of the Chief Justices Conference, the Resolution of which was sent by the Registrar says that a convention should be set up that when Commissions of Inquiry enquire into anything, their recommendations should be accepted. It is not that it asked for a commitment from the State Government. No such commitment was either asked for nor was given, as far as that particular matter was concerned. Ag far as Central responsibility ii concerned, I have . . .

SHRI BHUPESH GUPTA; On a point of order. I need protection.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I need your protection. He does not need your protection. You have called me to answer his question and I should be allowed to answer. As far ag the question of Central responsibility in this matter is concerned, I have several times, during the course of my previous replies here to-day, said that the Centres' responsibility, in this matter i-s not at all attracted.

SHRI BHUPESH GUPTA: Even assuming it was not done in an explicit manner, even in a private contract there are certain things implied as conditions. It is merely an implied condition. Suppose it was a contract between two parties and these documents are placed before a court of law, the contract would have been understood along with the two documents and these would have been taken as implied terms of the contract.

And the Government does not accept it as such. I am surprised that you should treat your Judges in this manner today.

MR. CHAIRMAN: What ii your point of order?

SHRI B. K. KAUL; When **the** Commission was appointed it was under the instructions, they Bay, of the Central Government. I would like to know what are the terms of reference of the Commission and whether the Judge has exceeded the terms of reference. *(Interruptions)* I understand that the Judge has made recommendations exceeding the terms of reference.

(Interruption)

MR. CHAIRMAN-. Nothing more. Calling-Attention. Mr. Rajnarain.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: I want to know only which is the book he is quoting frovn.

MR. CHAIRMAN: We have nothing to do with any book.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: He has quoted something.

MR. CHAIRMAN: I shall not allow any more on this matter. If he has quoted anything, it will be taken out.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: How can it be taken out?

SHRI BHUPEiSH GUPTA; We want to know whether it is the Telephone Directory in his hand.

MR. CHAIRMAN: Calling Attention to a matter of urgent public importance. Mr. Rajnarain.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair].

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ALLEGATIONS AGAINST FORMER CHIEF MINISTER OF PUNJAB

*555. SARDAR NARINDAR SINGH BRAR: SHRI SYED HUSSAIN:

Will the Minister of HOME AF-I FAIRS be pleased to state in the